भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4932
01 अप्रैल, 2025 को उत्तर के लिए
सजावटी मत्स्य निर्यात उद्योग

4932. श्री दुष्यंत सिंह:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि::

(क) क्या मंत्रालय बाजार हिस्सेदारी के संदर्भ में भारत के सजावटी मछली निर्यात उद्योग को बढ़ावा देता है और विश्व में 31वें सबसे बड़े निर्यातक के रूप में इसके स्थान में योगदान देने वाले प्रमुख कारक क्या हैं और उच्च संभावनाओं के बावजूद भारत के सजावटी मछली व्यापार की कम रैंकिंग को देखते हुए इसके लिए विकास की संभावनाएं क्या हैं;

(ख) वन्य किस्मों के निर्यात में पूर्वोत्तर और दक्षिणी राज्यों की क्या भूमिका है और राजस्थान तथा मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में नई उत्पादन इकाइयों ने उद्योग के विकास में किस प्रकार योगदान दिया है;

(ग) राजस्थान में बढ़ते सजावटी मत्स्यपालन क्षेत्र और विशेषकर प्रजनन कार्यक्रमों और वाणिज्यिक उत्पादन इकाइयों की स्थापना के बाद से प्रजनन और वाणिज्यिक उत्पादन में महत्वपूर्ण विकास का संदर्भ क्या है; और

(घ) बाजार किस प्रकार विकसित हुआ है और इस क्षेत्र में, विशेषकर अर्ध-शुष्क परिस्थितियों में, और अधिक वृद्धि की संभावना क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(श्री जॉर्ज कुरियन)

(क) से (घ) मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने पूर्वोत्तर और दक्षिणी राज्यों सहित देश में फिशरीस को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रयास किए हैं। प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत विगत चार वित्तीय वर्षों (2020-21 से 2023-24) और वर्तमान वित्तीय वर्ष (2024-25) के दौरान कुल 230.45 करोड़ रुपए की लागत से ओरनामेन्टल फिश रियरिंग यूनिट्स की 2465 यूनिट, 207 इन्टीग्रेटेड ऑर्नामेंटल फिश (ब्रीडिंग और रियरिंग) यूनिट्स, 5 फ्रेश वॉटर ओरनामेन्टल फिश ब्रूड बैंक यूनिट्स और मनोरंजक (रेक्रीऐशनल) मात्स्यिकी को बढ़ावा देने की 144 यूनिट्स को स्वीकृति दी गई है।

ओरनामेन्टल फिशरीस के क्षेत्र में उद्यमिता, इन्फ्रास्ट्रक्चर और मारकेट एक्सपेंशन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्यपालन विभाग भारत सरकार ने 2024- 25 के दौरान तमिलनाडु के मदुरै जिले को पीएमएमएसवाई के तहत ओरनामेन्टल फिशरीस क्लस्टर के रूप में अधिसूचित किया है। उत्तर भारत से ओरनामेन्टल फिश की देशी किस्म के प्रदर्शन के लिए अमिंगाव, कामरूप में एक एक्वेरियम के निर्माण के लिए असम सरकार के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त,देश में ऑर्नामेंटल मात्स्यिकी संसाधनों के विकास के लिए रणनीति और रोडमैप तैयार करने के लिए, पीएमएमएसवाई के तहत भारत में ऑर्नामेंटल फिशरीज वैल्यू चेन के अपग्रेडेशन की रणनीतिक योजना और डेटाबेस विकास के लिए आईसीएआर-सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेशवॉटर एक्वाकल्चर (ICAR-CIFA) के परियोजना प्रस्ताव को स्वाकृति दी गई।

प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत 2.60 करोड़ रुपए की लागत से ओरनामेन्टल फिश ब्रीडिंग और रियरिंग की 11 इकाईयों की स्थापना हेतु मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। फिशरीस एंड एक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट फंड (एफआईडीएफ) के तहत, 5.00 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ तिरुनेलवेली जिले के तिरुनेलवेली में एक सार्वजनिक एक्वेरियम और ओरनामेन्टल फिश रीटेल यूनिट की स्थापना के लिए तमिलनाडु सरकार के परियोजना प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) ने राजस्थान राज्य में ओरनामेन्टल फिशरीस को बढ़ावा देने के लिए 1000 प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करने के लिए ट्रापिकल एक्वाकल्चर एंड फारमिंग सिस्टम्स, उदयपुर, राजस्थान और राजस्थान सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान की है।

आईसीएआर- सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेशवॉटर एक्वाकल्चर (सीआईएफए), भुवनेश्वर ने सूचित किया है कि भारतीय ओरनामेन्टल फिश इंडस्ट्री का मूल्य लगभग 3,000 करोड़ रुपए है, जिसमें ब्रीडिंग और रियरिंग, ओरनामेन्टल फिश का व्यापार, एक्वेरियम के सामान, एक्वेटिक प्लांट और सजावटी सामान शामिल हैं, जो रोजगार और उद्यमिता में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ICAR-CIFA की रिपोर्ट के अनुसार , वर्तमान में मध्य प्रदेश में लगभग 1,300 एक्वेरियम दुकान और राजस्थान में 700 दुकान संचालित हैं।

*****